

1. राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनेरल मिशन (NCMM)



- 56 क्रिटिकल मिनेरल ब्लॉक और 11 अन्वेषण लाइसेंस ब्लॉक नीलाम।
- जनवरी 2025 में स्वीकृत; अवधि: 2024-25 से 2030-31।
- बजट: ₹16,300 करोड़ + PSU निवेश।
- अन्वेषण, खनन, प्रसंस्करण, रीसाइलिंग, R&D और कौशल विकास पर फोकस।
- EV, बैटरी, सेमीकंडक्टर, रक्षा एवं हरित ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण।
- प्रमुख खनिज: लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स।

मूल्य संवर्धन: MMDR (संशोधन) अधिनियम, 2023; भारत MSP (Minerals Security Partnership) का हिस्सा।

मुख्य शब्द: क्रिटिकल मिनेरल्स, NCMM, MSP, MMDR एक्ट

2. एल नीनो तैयारी एवं INCOIS विशेष बुलेटिन



- केन्द्र ने राज्यों के साथ खरीफ तैयारी की समीक्षा की।
- एल नीनो: प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग का असामान्य गर्म होना।
- प्रभाव: कमजोर मानसून, सूखा, फसल उत्पादन में कमी, खाद्य मुद्रास्फीति।
- INCOIS ने समुद्री क्षेत्रों के लिए विशेष एल नीनो बुलेटिन जारी किए।
- मत्स्य पालन, शिपिंग, तटीय संचालन और आपदा जोखिम में कमी में सहायक।

मूल्य संवर्धन: INCOIS मुख्यालय - हैदराबाद; ENSO और इंडियन ओशन डाइपोल (IOD) से जुड़ा।

मुख्य शब्द: एल नीनो, ENSO, IOD, INCOIS, खरीफ

3. NAFEX.in पोर्टल (NAFED)



- NAFED ने अपना ई-नीलामी पोर्टल NAFEX.in लॉन्च किया।
- कृषि विपणन को पारदर्शी बनाता है।
- किसानों के लिए बेहतर मूल्य खोज सुनिश्चित करता है।
- डिजिटल कृषि ट्रेडिंग इकोसिस्टम का निर्माण।
- एग्री-मार्केटिंग अवसरचना को सुदृढ़ करता है।
- किसानों की आय एवं मूल्य वास्तविकरण में सहायक।

मूल्य संवर्धन: NAFED की स्थापना 1958 में; मंत्रालय - सहकारिता मंत्रालय; मुख्यालय - नई दिल्ली।

मुख्य शब्द: NAFED, NAFEX, कृषि विपणन, ई-नीलामी

4. CPGRAMS मासिक रिपोर्ट



- DARPG ने मंत्रालयों तथा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की रिपोर्ट जारी की।
- CPGRAMS: केंद्रीय लोक शिकायत निवारण एवं मॉनिटरिंग प्रणाली।
- AI आधारित मॉनिटरिंग और विश्लेषण।
- पारदर्शिता, जवाबदेही और उत्तरदायित्व को बढ़ावा।
- मंत्रालयों का प्रदर्शन-आधारित मूल्यांकन एवं रैंकिंग।

मूल्य संवर्धन: DAPPG द्वारा प्रबंधित; नागरिक-केंद्रित सुशासन को सुदृढ़ करता है।

मुख्य शब्द: CPGRAMS, DARPG, सुशासन, जवाबदेही, AI

5. परिवहन, गतिशीलता एवं लॉजिस्टिक्स के लिए अर्थशास्त्र केंद्र



- NHAI और NCAER के बीच MoU हस्ताक्षरित।
- परिवहन अर्थशास्त्र, गतिशीलता और लॉजिस्टिक्स पर शोध को बढ़ावा।
- लॉजिस्टिक्स दक्षता और सतत परिवहन नियोजन में सहायता।
- सक्षम-आधारित नीति निर्माण को समर्थन।
- PM गति शक्ति एवं राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति से संबद्ध।
- भारत की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मंस इंडेक्स (2023) रैंक: 38।

मूल्य संवर्धन: NCAER - नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च।

मुख्य शब्द: लॉजिस्टिक्स, NHAI, NCAER, गति शक्ति, LPI

6. ग्रीन मैरीटाइम ग्रोथ एवं VOC पोर्ट



- VOC पोर्ट ने कार्बन उत्सर्जन में 45% की कमी हासिल की।
- VOC: V.O. चिदंबरनार पोर्ट, तूतीकोरिन, तमिलनाडु।
- हरित ऊर्जा, स्वच्छ संचालन और दक्षता पर फोकस।
- भारत के डीकार्बोनाइजेशन एवं ग्रीन शिपिंग में योगदान।
- मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के अनुरूप पहल।
- पोर्ट अवसरचना की स्थिरता को बढ़ाता है।

मूल्य संवर्धन: ग्रीन पोर्ट जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण और ब्लू इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण।

मुख्य शब्द: VOC पोर्ट, डीकार्बोनाइजेशन, ग्रीन शिपिंग, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030

7. INS तारकाश का मॉरीशस दौरा एवं पूर्वी बेड़े का वियतनाम दौरा



- INS तारकाश (शिवालिक श्रेणी का स्टेल्थ क्रिगेट) मॉरीशस गया।
- भारतीय पूर्वी बेड़े के जहाज उदयगिरि और कावस्ती वियतनाम पहुंचे।
- समुद्री कूटनीति और रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करता है।
- एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो-पैसिफिक विजन को बल।
- क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा।
- SAGAR (Security And Growth for All in the Region) सिद्धांत का प्रतीक।

मूल्य संवर्धन: SAGAR - क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास।

मुख्य शब्द: INS तारकाश, SAGAR, इंडो-पैसिफिक, समुद्री कूटनीति, एक्ट ईस्ट पॉलिसी

8. पंचायतों के माध्यम से नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण



- पंचायती राज मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित।
- नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण में सुधार पर फोकस।
- पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका को सुदृढ़ करना।
- स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना और समावेशी विकास को बढ़ावा।
- विकेंद्रीकरण और भागीदारीपूर्ण शासन को प्रोत्साहन।
- संवैधानिक आधार: 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992।

मूल्य संवर्धन: PESA अधिनियम, 1996 जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभा को सशक्त बनाता है।

मुख्य शब्द: पंचायती राज, विकेंद्रीकरण, 73वां संशोधन, PESA, समावेशी विकास

9. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (PIB पूछभूमि सामग्री)



- बच्चों के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान।
- आयु वर्ग: 5 से 18 वर्ष।
- श्रेणियाँ: साहसिकता, खेल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, कला एवं संस्कृति।
- पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है।
- नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से।

मूल्य संवर्धन: उत्कृष्टता को मान्यता देता है और बच्चों को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करता है।

मुख्य शब्द: प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, बच्चे, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल

अन्य महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ (One-Liners)

प्रधानमंत्री ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि दी।

प्रधानमंत्री ने 2024 वैच के IAS प्रशिक्षुओं से सहायक सचिव के रूप में बातचित की।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक आंदोलन के रूप में उभरा।

पीएफ नियंत्रक कार्यालय, दिल्ली ने पेंशन अदालत का सफल आयोजन किया।

IEPFA ने 'Claiming the Unclaimed' पुस्तक पर चर्चा की।

भारतीय नौसेना के जहाज हो ची भिन् मित्ठी (वियतनाम) पहुंचे।

CCI ने Alpha Wave Ventures और Honda Motor Co. Ltd के अधिग्रहण को मंजूरी दी।

औषधि विभाग ने GTE छूट सूची में संशोधनों पर हितधारकों से टिप्पणी आमंत्रित की।

1. National Critical Mineral Mission (NCMM)

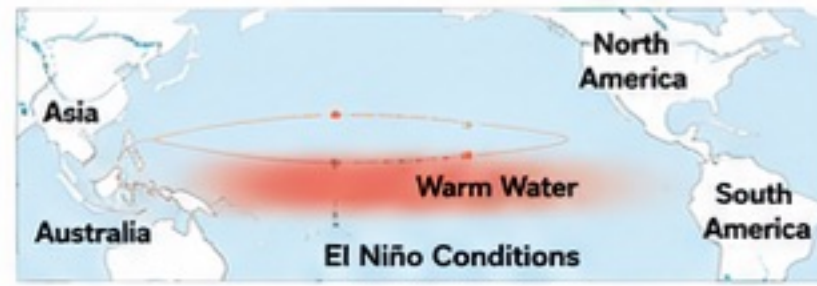


- 56 Critical Mineral Blocks & 11 Exploration Licence Blocks auctioned.
- Approved in Jan 2025; period: 2024-25 to 2030-31.
- Outlay: ₹16,300 crore + PSU investments.
- Covers exploration, mining, processing, recycling, R&D and skilling.
- Supports EVs, batteries, semiconductors, defence.
- Minerals: Lithium, Cobalt, Nickel, Graphite, Rare Earth Elements.

Value Addition: MMDR (Amendment) Act, 2023; India part of Minerals Security Partnership (MSP).

Keywords: Critical Minerals, NCMM, MSP, MMDR Act

2. El Niño Preparedness & INCOIS Special Bulletins



- Centre reviewed Kharif preparedness with States.
- El Niño: abnormal warming of eastern Pacific Ocean.
- Impacts: weak monsoon, drought, lower crop yields, food inflation.
- INCOIS launched Special El Niño Bulletins for maritime sectors.
- Helps fisheries, shipping, coastal operations & disaster risk reduction.

Value Addition: INCOIS HQ – Hyderabad; Linked to ENSO and Indian Ocean Dipole (IOD).

Keywords: El Niño, ENSO, IOD, INCOIS, Kharif

3. NAFEX.in Portal of NAFED



- NAFED launched e-auction portal NAFEX.in.
- Promotes transparent agricultural marketing.
- Ensures better price discovery for farmers.
- Creates digital trading ecosystem.
- Strengthens agri-marketing infrastructure.
- Supports farmer income & value realisation.

Value Addition: NAFED established in 1958; Ministry – Ministry of Cooperation; HQ – New Delhi.

Keywords: NAFED, NAFEX, Agri Marketing, E-Auction

4. CPGRAMS Monthly Reports



- DARPG released reports for Ministries & States/UTs.
- CPGRAMS: Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System.
- AI-enabled monitoring & analytics.
- Enables transparency, accountability & responsiveness.
- Ranks Ministries based on performance.

Value Addition: Managed by DAPRG; Strengthens citizen-centric governance.

Keywords: CPGRAMS, DARPG, Good Governance, Accountability

5. Centre for Economics of Transportation, Mobility & Logistics



- MoU signed between NHA & NCAER.
- Centre will promote research in transport economics.
- Aims to improve logistics efficiency & mobility planning.
- Supports evidence-based policy making.
- Linked to PM Gati Shakti & National Logistics Policy.
- India's Logistics Performance Index (2023): Rank 38.

Value Addition: NCAER – National Council of Applied Economic Research.

Keywords: Logistics, NHA, NCAER, Gati Shakti, LPI

6. Green Maritime Growth & VOC Port



- VOC Port achieved 45% reduction in carbon emissions.
- VOC: V.O. Chidambaranar Port, Thoothukudi, TN.
- Focus on green energy, clean operations & efficiency.
- Supports India's decarbonization & green shipping.
- Aligns with Maritime India Vision 2030.
- Enhances sustainability of port infrastructure.

Value Addition: Green ports crucial for climate action & blue economy.

Keywords: VOC Port, Decarbonization, Green Shipping, Maritime India Vision 2030

7. INS Tarkash in Mauritius & Eastern Fleet Visit to Vietnam

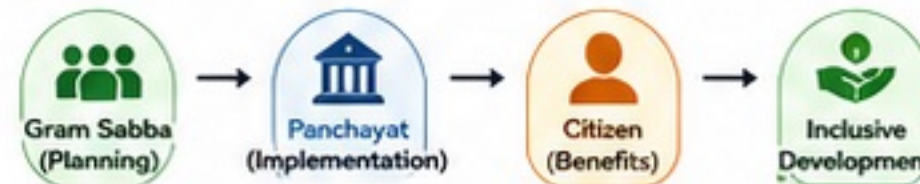


- INS Tarkash (Shivalik-class stealth frigate) in Mauritius.
- Eastern Fleet ships Udaygiri & Kavaratti arrive Vietnam.
- Strengthens maritime diplomacy & defence ties.
- Reinforces India's Act East Policy & Indo-Pacific vision.
- Promotes regional peace, stability & cooperation.
- Embodies SAGAR doctrine.

Value Addition: SAGAR – Security And Growth for All in the Region.

Keywords: SAGAR, Indo-Pacific, INS Tarkash, Maritime Diplomacy, Act East Policy

8. Citizen-Centric Service Delivery Through Panchayats



- MoPR conducted regional workshop.
- Focus on improving citizen-centric service delivery.
- Strengthens role of Panchayati Raj Institutions.
- Empowering local bodies for inclusive development.
- Promotes decentralization & participatory governance.
- Constitutional Link: 73rd Amendment Act, 1992.

Value Addition: PESA Act, 1996 empowers Gram Sabhas in tribal areas.

Keywords: Panchayati Raj, Decentralization, 73rd Amendment, PESA

9. Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar (PIB Backgrounder)



- Highest civilian honour for children in India.
- Age group: 5 to 18 years.
- Categories: Bravery, Sports, Science & Technology, Social Service, Environment, Art & Culture.
- Conferred by the President of India.
- Nominations through National Awards Portal.

Value Addition: Recognizes excellence & inspires children across the country.

Keywords: PM Rashtriya Bal Puraskar, Children, National Awards, President of India

Other Important One-Liners

PM pays homage to Dr. Syama Prasad Mookerjee on his Balidan Diwas.

PM interacts with IAS Officer Trainees of 2024 Batch posted as Assistant Secretaries.

International Day of Yoga 2026 under leadership of PM Modi.

Office of Pr. CCA, Delhi organises Pension Adalat successfully.

IEPFA discusses idle financial assets; book "Claiming the Unclaimed" launched.

Indian Navy ships arrive Ho Chi Minh City, Vietnam.

CCI approves acquisition in Alpha Wave Ventures and Honda Motor Company.

Dept. of Pharmaceuticals invites stakeholder comments on GTE exemption list.

21 जून 2026 (शनिवार)

तेलंगाना

काकतीयों की धरोहर • नवाचार की शक्ति • संस्कृति की पहचान



रामप्पा मंदिर (यूनेस्को स्थल)

3. इतिहास एवं विरासत

- प्राचीन इतिहास**
सातवाहन, विष्णुकुंडिन आदि ने शासन किया।
- मध्यकालीन इतिहास**
 - काकतीय वंश (12वीं-14वीं शताब्दी)
राजधानी - वरंगल
 - कुचुब शाही वंश (16वीं-17वीं शताब्दी)
 - हैदराबाद की स्थापना (1591)
 - चारमिनार, गोलकोंडा किला
- आधुनिक इतिहास**
 - तेलंगाना आंदोलन - अलग राज्य की मांग
 - 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन
- महत्वपूर्ण स्मारक**
काकतीय कला तोरणम, हजार स्तंभ मंदिर, चारमिनार, गोलकोंडा किला
- यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल**
रामप्पा मंदिर (2021 में शामिल)



चारमिनार



काकतीय कला तोरणम, वरंगल



हजार स्तंभ मंदिर, हैनामकोंडा

2. स्थान एवं भौगोलिक स्वरूप



पड़ोसी राज्य

- महाराष्ट्र
- छत्तीसगढ़
- आंध्र प्रदेश
- कर्नाटक

मुख्य नदियाँ

- गोदावरी
- कृष्णा
- मुत्सी
- मंजीरा
- प्राणहिता

भौगोलिक क्षेत्र

- तेलंगाना पठार
- गोदावरी बेसिन
- कृष्णा बेसिन

1. त्वरित तथ्य

- राजधानी : हैदराबाद
- गठन : 2 जून 2014
- राजभाषाएं : तेलुगु, उर्दू
- राज्य पशु : चीतल (स्पॉटिड डियर)
- राज्य पक्षी : भारतीय नीलकंठ
- राज्य पुष्प : तांगेडु फूल
- राज्य वृक्ष : जमी पेड़
- जनसंख्या (2011) : 3.50 करोड़ (लगभग)
- क्षेत्रफल : 1,12,077 वर्ग कि.मी.
- साक्षरता दर : 66.46%

महत्वपूर्ण तथ्य

- भारत का 28वां राज्य
- हैदराबाद - साइबराबाद के नाम से प्रसिद्ध
- रामप्पा मंदिर (2021) यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल
- कालेश्वरम परियोजना - विश्व की सबसे बड़ी लिफ्ट इरीगेशन परियोजना

4. अर्थव्यवस्था

- मुख्य उद्योग**
आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण
- प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र**
हाइटेक सिटी, साइबराबाद, जीनोम वैली, फार्मा सिटी
- खनिज संपदा**
चुना पत्थर, कोयला, डोलोमाइट, ब्रेनाइट, क्वाटेज़
- बुनियादी ढांचा**
ORR, मेट्रो रेल (हैदराबाद), राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, मल्टीमॉडल परिवहन
- विशेष तथ्य**
हैदराबाद - भारत के प्रमुख आईटी और नवाचार केंद्रों में से एक।



हाइटेक सिटी, हैदराबाद



फार्मा सिटी, संगारेड्डी

5. कृषि

- मुख्य फसलें**
धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, दालें, कपास, मिर्च, हल्दी
- बागवानी फसलें**
आम, पपीता, अनार, नींबू, संतरा, केला
- पशुपालन**
गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी पालन
- GI टैग उत्पाद**
पोचमपल्ली इकट, गडवाल साड़ियाँ, नारायणपेट साड़ियाँ
- विशेष उत्पाद**
हल्दी, मिर्च, कपास, आम



धान का खेत



हल्दी



आम



कपास

कालेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन परियोजना - विश्व की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई योजना

6. संस्कृति एवं परंपरा

- लोक नृत्य**
पेरिनी शिवतांडवम, लम्बाड़ी नृत्य, ओगु कथा
- लोक संगीत**
बत्कम्मा गीत, बुरकथा
- कला रूप**
निर्मल पेंटिंग, चेरियल स्कोल पेंटिंग
- हस्तशिल्प**
पोचमपल्ली इकट, बिठरीवेयर, निर्मल पेंटिंग, डोकरा कला
- भाषाएँ**
तेलुगु, उर्दू
- सांस्कृतिक विशेषताएँ**
समृद्ध वास्तवीय संस्कृति, मेहमाननवाजी, त्योहारों में सामुदायिक भागीदारी



पेरिनी शिवतांडवम



निर्मल पेंटिंग

7. प्रमुख त्योहार

- बातुकम्मा (फूलों का त्योहार)
- बोनालू (देवी महाकाली की उपासना)
- संक्रांति
- उगादी
- दशहरा
- ईद
- मुहर्रम



बातुकम्मा उत्सव

8. पर्यावरण एवं जैव विविधता

- राष्ट्रीय उद्यान**
मुगाचनी राष्ट्रीय उद्यान
- टाइगर रिजर्व**
अमराबाद टाइगर रिजर्व, क्वाल टाइगर रिजर्व
- वन्यजीव अभयारण्य**
एन्पूतम वन्यजीव अभयारण्य, पोचरम वन्यजीव अभयारण्य
- रामसर स्थल**
पाकर झील (महबुबनगर)
- महत्वपूर्ण वन्यजीव**
बाघ, तेंदुआ, चीतल, नीलगाय, भारतीय नीलकंठ, रसोई भालू



अमराबाद टाइगर रिजर्व



भारतीय नीलकंठ



चीतल



एन्पूतम वन्यजीव अभयारण्य

10. UPSC के लिए मुख्य संवर्धन

- प्रिलिम्स तथ्य:** 28वां राज्य, राजधानी हैदराबाद, रामप्पा मंदिर (यूनेस्को), भारतीय नीलकंठ (राज्य पक्षी), कालेश्वरम परियोजना
- मुख्य बिंदु (निबंध/मेल्स):** जल प्रबंधन, क्षेत्रीय असमानता, कृषि परिवर्तन, आईटी और नवाचार, शहरीकरण
- करेंट अफेयर्स लिंक:** सेमीकंडक्टर नीति, फार्मा सिटी, मिशन भगीरथा, KCR सरकार की योजनाएँ
- रणनीतिक महत्व:** दक्कन क्षेत्र का केंद्र, कृषि और उद्योग का संतुलन, आईटी और फार्मा हब, दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार
- महत्वपूर्ण व्यक्तित्व:** कोमरम भीम, सरदार वल्लभभाई पटेल (हैदराबाद एकीकरण), प्रो. जयशंकर (तेलंगाना आंदोलन)

11. त्वरित पुनरावृत्ति - 15 एक पंक्ति तथ्य

- गठन - 2 जून 2014
- राजधानी - हैदराबाद
- राजभाषाएँ - तेलुगु, उर्दू
- राज्य पशु - चीतल
- राज्य पक्षी - भारतीय नीलकंठ
- राज्य पुष्प - तांगेडु फूल
- राज्य वृक्ष - जमी पेड़
- सबसे ऊँची चोटी - डोली गुटा
- मुख्य नदियाँ - गोदावरी, कृष्णा
- यूनेस्को स्थल - रामप्पा मंदिर (2021)
- प्रमुख त्योहार - बातुकम्मा, बोनालू
- प्रमुख उद्योग - आईटी, फार्मा
- प्रमुख परियोजना - कालेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन
- प्रसिद्ध स्मारक - चारमिनार, गोलकोंडा किला
- टाइगर रिजर्व - अमराबाद, कवाल

12. तेलंगाना एक नज़र में

<p>युवतम राज्य (2014)</p>	<p>आईटी एवं फार्मा पावरहाउस</p>	<p>समृद्ध सांस्कृतिक विरासत</p>
<p>कृषि एवं सिंचाई में प्रगति</p>	<p>जल सुरक्षा - मिशन भगीरथा</p>	<p>परंपरा और नवाचार का संगम</p>

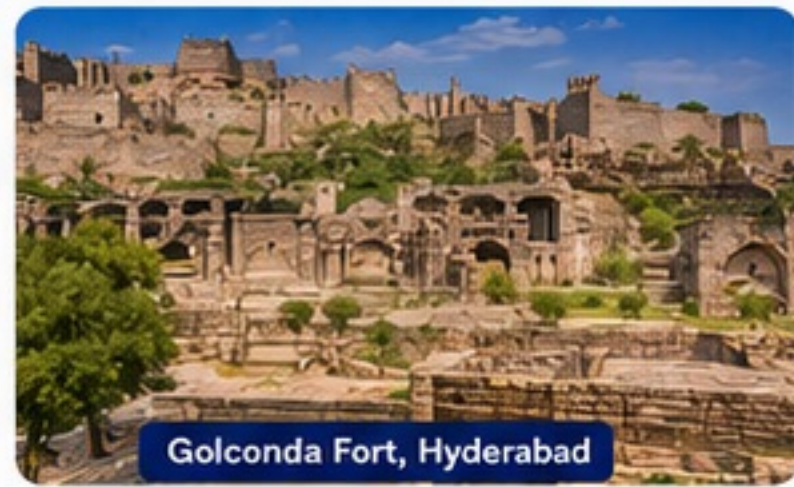
SRIJAN INDIA ONE

KNOW YOUR STATE

21ST JUNE 2026

TELANGANA

Heritage of Kakatiyas • Powerhouse of Innovation • Culture of Pride



Golconda Fort, Hyderabad



Ramappa Temple (UNESCO Site)

1. QUICK FACTS

Capital	: Hyderabad
Formation	: 2 June 2014
Official Languages	: Telugu, Urdu
State Animal	: Spotted Deer
State Bird	: Indian Roller
State Flower	: Tangedu Flower
State Tree	: Jammi Tree
Population (2011)	: 3.50 Crore
Area	: 1,12,077 sq. km
Literacy Rate	: 66.46%

IMPORTANT FACTS

- ★ 28th State of India
- ★ Hyderabad – Cyberabad is an IT Hub
- ★ Home to Ramappa Temple (UNESCO Site)
- ★ Kaleshwaram Project – World's largest Lift Irrigation Scheme

2. LOCATION & GEOGRAPHY



3. HISTORY & HERITAGE

- Ancient History**
Region of Satavahanas and Vishnukundins
- Medieval History**
Kakatiya Dynasty (12th–14th Century)
Capital: Warangal
Built Thousand Pillar Temple, Warangal Fort
- Qutb Shahi Dynasty**
(16th–17th Century)
Built Charminar and Golconda Fort
- Modern History**
Telangana Movement for separate statehood
State formed on 2 June 2014
- UNESCO Heritage Site**
Ramappa Temple (Inscribed in 2021)



Charminar, Hyderabad



Kakatiya Kala Thoranam, Warangal



Thousand Pillar Temple, Hanamkonda

4. ECONOMY

- Major Industries**
IT, Pharmaceuticals, Biotechnology, Electronics, Textiles, Food Processing
- Key Hubs**
Hyderabad (Cyberabad), HITEC City, Genome Valley, Pharma City
- Minerals**
Limestone, Coal, Barytes, Quartz
- Infrastructure**
ORR, Regional Ring Road, Hyderabad Metro, Multi-modal transport
- Airports**
Rajiv Gandhi International Airport, Hyderabad



HITEC City, Hyderabad



Pharma City, Sangareddy

5. AGRICULTURE

- Major Crops**
Rice, Maize, Jowar, Pulses, Cotton, Chillies, Turmeric, Oilseeds
- Horticulture**
Mango, Guava, Papaya, Pomegranate, Lemon
- Livestock**
Cattle, Buffalo, Sheep, Goat, Poultry
- GI Tags**
Pochampally Ikat, Gadwal Sarees, Narayanpet Sarees
- Special Products**
Turmeric, Red Gram, Mango, Cotton



Paddy Field



Turmeric



Mango



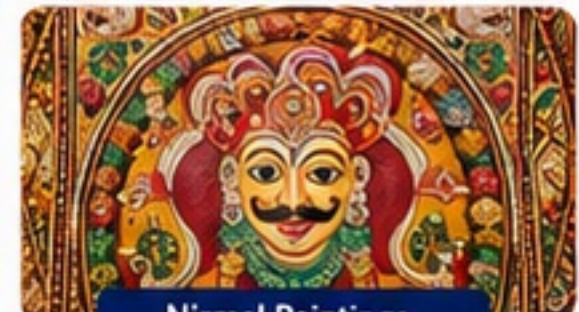
Cotton

6. CULTURE & TRADITION

- Folk Dances**
Perini Shivatandavam, Lambadi Dance, Oggu Katha
- Folk Music**
Bathukamma Songs, Oggu Katha, Burrakatha
- Art Forms**
Nirmal Paintings, Cherial Scroll Paintings, Puppet Making
- Handicrafts**
Bidriware, Pochampally Ikat, Bamboo Craft, Dokra Art
- Languages**
Telugu, Urdu
- Cultural Practices**
Hospitality, Bathukamma Tradition, Bonalu Culture



Perini Shivatandavam



Nirmal Paintings

7. FESTIVALS

- Bathukamma (Floral Festival)
- Bonalu (Traditional Festival)
- Sankranti
- Ugadi
- Dasara
- Eid
- Muharram



Bathukamma Festival

8. ENVIRONMENT & BIODIVERSITY

- Tiger Reserves**
Amrabad, Kawal
- National Parks**
Mahavir Harina Vanasthali (Park for Deer)
- Wildlife Sanctuaries**
Eturnagaram, Pocharam, Manjeera
- Biosphere Reserves**
None
- Ramsar Sites**
None
- Important Species**
Tiger, Leopard, Sloth Bear, Spotted Deer, Indian Roller, Blackbuck



Amrabad Tiger Reserve



Indian Roller



Spotted Deer



Eturnagaram Wildlife Sanctuary

9. TOURISM & HERITAGE

- Major Attractions**
Charminar, Golconda Fort, Ramappa Temple, Kakatiya Kala Thoranam, Thousand Pillar Temple
- Religious Sites**
Yadadri Temple, Bhadrachalam Temple, Basar Saraswati Temple
- Cultural Landmarks**
Birla Mandir, Chowmahalla Palace, Salar Jung Museum
- UNESCO Site**
Ramappa Temple



Charminar



Bhadrachalam Temple



Yadadri Temple



Birla Mandir

10. UPSC VALUE ADDITION

- Prelims Facts**
28th State, Formed in 2014, Ramappa Temple (UNESCO), State Bird – Indian Roller
- Mains Points**
Water management (Kaleshwaram), IT growth, Pharma hub, Agriculture transformation, Regional disparities
- Current Affairs Linkages**
Semiconductor ecosystem, Hyderabad as Global City, Pharma exports, Mission Kakatiya
- Important Personalities**
Koloji Narayana Rao, Komaram Bheem (Tribal Leader), Suravaram Pratap Reddy
- Strategic Importance**
Central location in Deccan, Industrial corridor, IT and Pharma powerhouse

11. RAPID REVISION – 15 KEY FACTS

- Formation – 2 June 2014
- Capital – Hyderabad
- Official Languages – Telugu, Urdu
- State Animal – Spotted Deer
- State Bird – Indian Roller
- State Flower – Tangedu Flower
- State Tree – Jammi Tree
- Major Rivers – Godavari, Krishna
- UNESCO Site – Ramappa Temple
- Dynasty – Kakatiya Dynasty
- Major Festival – Bathukamma
- Irrigation Project – Kaleshwaram
- IT Hub – Cyberabad
- GI Tags – Pochampally Ikat, Gadwal Sarees, Narayanpet Sarees
- Tiger Reserves – Amrabad, Kawal

12. TELANGANA AT A GLANCE

Youngest State (2014)	IT & Pharma Powerhouse	Rich Cultural Heritage
Agricultural Diversity	Water Security (Mission Kakatiya)	Heritage Meets Innovation

प्रश्न: मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य उच्च आचरण एवं व्यवहार मानकों को बनाए रखना है ताकि नागरिकों की सेवा में दक्षता सुनिश्चित हो और स्वयं का विकास भी हो। यह योजना सिविल सेवकों को उत्पादक दक्षता बढ़ाने और जमीनी स्तर पर सेवाएँ प्रदान करने के लिए किस प्रकार सशक्त बनाती है? **चर्चा कीजिए।**

1 परिचय

- मिशन कर्मयोगी की शुरुआत वर्ष 2020 में NPCSCB के अंतर्गत।
- उद्देश्य: सिविल सेवकों को "रूल-बेस्ड" से "रोल-बेस्ड" प्रशासक बनाना।
- मूल्य: सेवा, समर्पण, संवेदनशीलता, सत्यनिष्ठा, नवाचार।

2 अवधारणा / परिभाषा

- भारत सरकार का क्षमता निर्माण कार्यक्रम।
- सतत् अधिगम (Continuous Learning) एवं कौशल विकास पर आधारित।
- iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल अधिगम।

3 पृष्ठभूमि

- भारत में बड़े पैमाने पर नौकरशाही: लगभग 48 लाख+ कर्मचारी।
- आधुनिक चुनौतियाँ: जटिल नीतियाँ, तकनीकी परिवर्तन, नागरिक अपेक्षाएँ।
- समग्र विकास हेतु: कौशल + मूल्य + दृष्टिकोण।

4 कारण / विशेषताएँ / आवश्यकता

- जटिल शासन चुनौतियाँ एवं बढ़ती नागरिक अपेक्षाएँ।
- तेजी से तकनीकी परिवर्तन एवं नीति आवश्यकताएँ।
- दक्षता, जवाबदेही एवं संवेदनशीलता की आवश्यकता।
- विशेषताएँ: दक्षता आधारित, सतत् अधिगम, 4E मॉडल (End-to-End, Enhanced, Ease of Access, Equity)

5 प्रवाह-चित्र (Flowchart)



6 मानचित्र (Maps)



7 आरेख - 4E मॉडल



8 उदाहरण

- भारत के उदाहरण**
- आकांक्षी जिला कार्यक्रम
 - पीएम-किस्सन - DBT क्रियान्वयन
 - पोषण अभियान
- अंतरराष्ट्रीय उदाहरण**
- सिंगपुर - Whole-of-Government दृष्टिकोण
 - UK - Civil Service Learning Platform
- हालिया उदाहरण**
- iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर 50 लाख+ नामांकित शिक्षार्थी

1 विश्लेषण

- कौशल, ज्ञान एवं सही दृष्टिकोण से युक्त सिविल सेवक।
- नैतिक आचरण, सत्यनिष्ठा एवं जवाबदेही को बढ़ावा।
- बेहतर निर्णय क्षमता, नवाचार एवं समस्या समाधान।
- अंतिम चरण तक प्रभावी सेवा वितरण एवं नागरिक संतुष्टि।

2 चुनौतियाँ

- डिजिटल विभाजन एवं विविध तकनीकी साक्षरता।
- व्यवहार परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध।
- निचले स्तर की नौकरशाही में क्षमता निर्माण की कमी।
- मगवूत मॉनिटरिंग एवं फीडबैक तंत्र की आवश्यकता।

3 प्रभाव / परिणाम

- सार्वजनिक सेवाओं में उच्च दक्षता एवं उत्पादकता।
- नागरिकों एवं सरकार के बीच विश्वास में वृद्धि।
- नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन एवं समावेशी विकास।
- लोकतंत्र एवं सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करना।

4 केस स्टडी

- आकांक्षी जिला कार्यक्रम - तालमेल, नवाचार एवं परिणाम।
- ई-कोर्ट मिशन - तकनीक के उपयोग से दक्षता।
- कोविड-19 प्रबंधन - प्रशिक्षित नौकरशाही की महत्वपूर्ण भूमिका।
- स्वच्छ भारत मिशन - जमीनी स्तर पर जनसहभागिता।

5 रिपोर्ट / समितियाँ

- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) - क्षमता निर्माण पर बल।
- नीति आयोग - Strategy for New India @75।
- आर.सी. अग्रवाल समिति - सिविल सेवा सुधार।

6 सरकारी पहल

- iGOT कर्मयोगी - डिजिटल अधिगम प्लेटफॉर्म।
- राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (NPCSCB)।
- मिशन मोड परियोजनाएँ एवं थीमेटिक प्रशिक्षण कार्यक्रम।

7 आगे की राह (Way Forward)



8 निष्कर्ष

- मिशन कर्मयोगी सिविल सेवकों को सक्षम, नैतिक एवं नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में एक परिवर्तनकारी पहल है।
- यह उत्पादक दक्षता बढ़ाकर जमीनी स्तर पर सेवाओं की गुणवत्ता एवं पहुँच को सुनिश्चित करता है।
- यह सुशासन, समावेशी विकास एवं विकसित भारत @2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक है।

मूल्य-संवर्धन (Value Addition)

- नैतिकता, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता
- जवाबदेही, संवेदनशीलता, समर्पण
- नागरिक-केंद्रित प्रशासन
- सतत् अधिगम, नवाचार, सहयोग

कीवर्ड्स

- क्षमता निर्माण
- भूमिका आधारित प्रशासन
- उत्पादक दक्षता
- सतत् अधिगम
- नागरिक-केंद्रित सेवा

महत्वपूर्ण शब्द

- कर्मयोगी
- NPCSCB
- iGOT प्लेटफॉर्म
- 4E मॉडल
- Whole-of-Government

संविधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 309 - सेवाओं की भर्ती
- अनुच्छेद 310 - कार्यकाल
- अनुच्छेद 311 - सेवा सुरक्षा
- अनुच्छेद 14 - समानता का अधिकार
- अनुच्छेद 51A - नागरिक कर्तव्य

महत्वपूर्ण समितियाँ

- द्वितीय ARC (2005)
- आर.सी. अग्रवाल समिति (2006)
- होटा समिति (2004)
- नीति आयोग - Strategy for New India @75

महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स

- द्वितीय ARC रिपोर्ट
- नीति आयोग रिपोर्ट;
- आर्थिक सर्वेक्षण
- UN E-Government Survey

Q. Mission Karmayogi aims to ensure a very high standard of conduct and behaviour to ensure efficiency in serving citizens and in turn developing oneself. **Discuss** how this scheme empowers civil servants in enhancing productive efficiency and delivering services at the grassroots level.

1 INTRODUCTION

- Mission Karmayogi launched in 2020 under NPCSCB.
- Vision: Transform civil servants into 'Karmayogis' – capable, ethical and citizen-centric.
- Aligns with values of Seva, Samarpan, Samman, Imaandari.

2 CONCEPT / DEFINITION

- Capacity building program of Government of India.
- Seeks to shift from Rule-based to Role-based administration.
- Continuous learning through iGOT Karmayogi platform.

3 BACKGROUND

- India's large bureaucracy: 48 lakh+ employees.
- Need for mindset change, skill upgrade and ethical conduct.
- Focus on holistic development: skills + values + attitude.

4 CAUSES / FEATURES / NEED

- Complex governance challenges & citizen expectations.
- Rapid tech changes & evolving policy needs.
- Need for competence, accountability & empathy.
- Features: Competency-based, Continuous learning, 4E model (End-to-End, Enhanced, Ease of access, Equity).

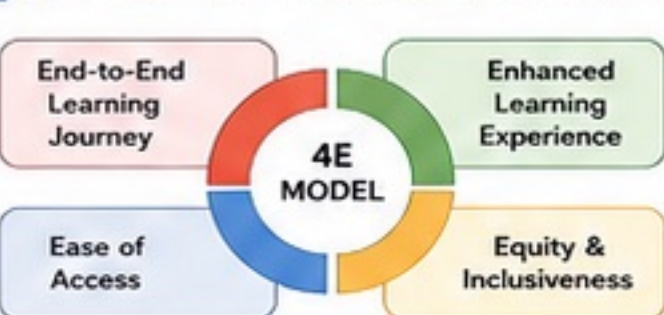
5 FLOWCHART



6 MAPS



7 DIAGRAM - 4E MODEL OF MISSION



8 EXAMPLES

- India Examples**
- Aspirational Districts Programme
 - PM-KISAN - DBT implementation
 - Poshan Abhiyaan
- International Examples**
- Singapore - Whole-of-Government approach
 - UK - Civil Service Learning Platform
- Recent Example**
- iGOT Karmayogi platform crossed 50 lakh+ enrollees

1 ANALYSIS

- Empowers civil servants with skills, knowledge & right attitude.
- Promotes ethical behaviour, integrity & accountability.
- Enhances decision-making, innovation & problem-solving.
- Strengthens last-mile delivery & citizen satisfaction.

2 CHALLENGES

- Digital divide & varying tech literacy.
- Resistance to behavioural change.
- Ensuring last-mile capacity building.
- Need for robust monitoring & feedback.

3 IMPLICATIONS

- Higher efficiency & productivity in public services.
- Increased trust between citizens and government.
- Better policy implementation & inclusive growth.
- Strengthens democracy and social cohesion.

4 CASE STUDIES

- Aspirational Districts Programme - convergence and outcomes.
- e-Courts Mission - use of technology for efficiency.
- COVID-19 Management - role of trained bureaucracy.
- Swachh Bharat Mission - grassroots mobilization.

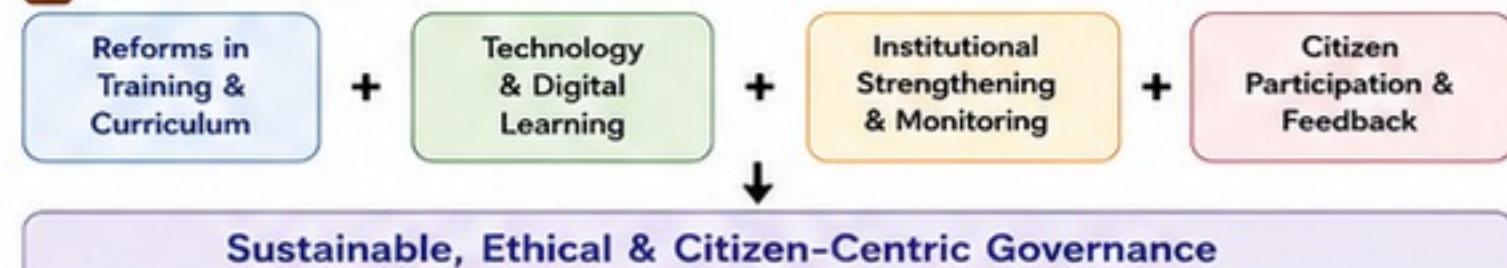
5 REPORTS / COMMITTEES

- 2nd Administrative Reforms Commission (ARC) - Capacity building emphasized.
- NITI Aayog - Strategy for New India @75.
- R.C. Agarwal Committee - Civil Services Reforms.

6 GOVERNMENT INITIATIVES

- iGOT Karmayogi - Digital learning platform.
- National Programme for Civil Services Capacity Building.
- Mission-mode projects & thematic training programs.

7 WAY FORWARD



8 CONCLUSION

- Mission Karmayogi is a transformational step towards building a competent, ethical and citizen-centric bureaucracy.
- It empowers civil servants to deliver efficient services with integrity and empathy.
- This strengthens governance, enhances trust and contributes to Viksit Bharat @2047.

VALUE ADDITION

- Keywords
- Important Terms
- Reports
- Committees
- Constitutional Articles
- Examples
- Case Studies

KEYWORDS

- Capacity Building
- Competence
- Accountability
- Citizen-Centric
- Ethics
- Efficiency
- Inclusion

IMPORTANT TERMS

- Karmayogi
- Role-based Administration
- Continuous Learning
- Ethical Governance
- Grassroots Delivery
- Public Service Values

CONSTITUTIONAL PROVISIONS

- Article 309 - Recruitment & conditions of service
- Article 310 - Tenure of office
- Article 311 - Protection of service
- Article 14 - Equality before law
- Article 21 - Right to life (includes dignified public services)

IMPORTANT COMMITTEES

- 2nd ARC (2005)
- R.C. Agarwal Committee (2006)
- Hota Committee (2004)
- NITI Aayog - Strategy for New India @75

IMPORTANT REPORTS

- 2nd ARC Report
- NITI Aayog Report
- Economic Survey
- UN E-Government Survey

1 P has a son and a daughter. S is the mother of T. S is R's spouse. Q and R are children of P. Then how is Q related to S?

- (a) Q is a sister of S (b) Q is a daughter of S
(c) Q is the mother of S (d) Q is a sister of the husband of S

SOLUTION

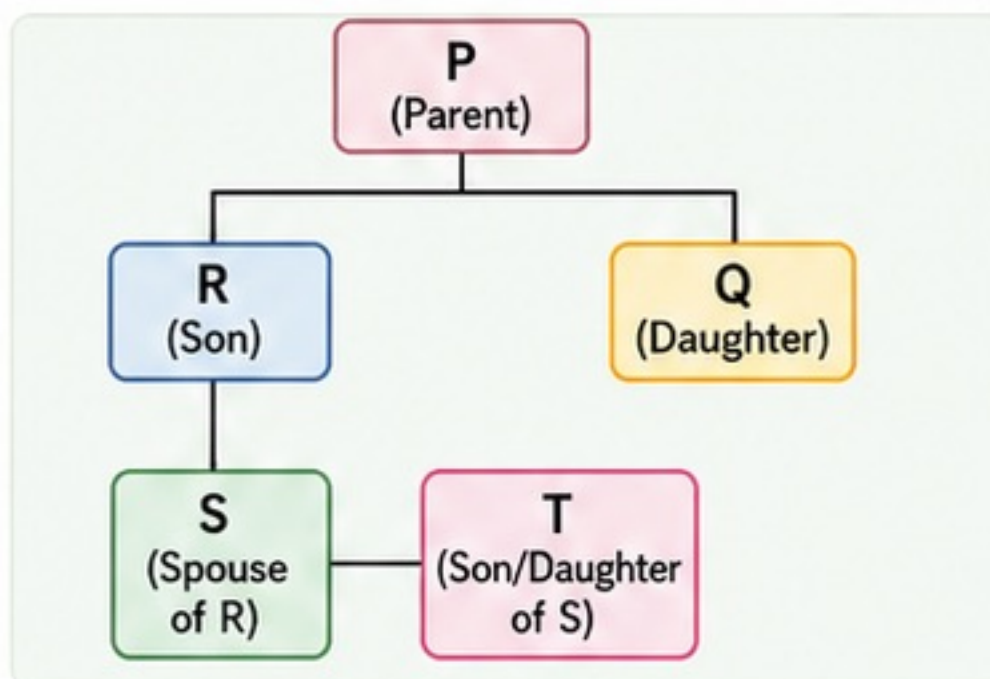
1 Idea / Approach

- Identify genders and draw family tree.

2 Key Observation

- S is the mother of T \Rightarrow S is female.
- S is R's spouse \Rightarrow R is male.
- P has one son and one daughter.
- Q and R are children of P.

3 Step-by-step Solution



From the tree:

- R is son of P.
- Q is daughter of P.
- S is wife of R.
- Q is sister of R.

4 Shortcut / CSAT Trick

- If two people are children of the same parent and one is spouse of a person, the other child is sibling-in-law of that person.

5 Final Answer

ANSWER: (d) Q is a sister of the husband of S

2 How many three-digit numbers can be expressed as an integral power of 2?

- (a) 1 (b) 2
(c) 3 (d) 4

SOLUTION

1 Idea / Approach

- Find powers of 2 that fall in the range of three-digit numbers (100 to 999).

2 Key Observation

- Three-digit numbers are from 100 to 999.

3 Step-by-step Solution

Power (n)	2^n	Value	Three-digit?
2^0	1	1	No
2^1	2	2	No
2^2	4	4	No
2^3	8	8	No
2^4	16	16	No
2^5	32	32	No
2^6	64	64	No
2^7	128	128	Yes
2^8	256	256	Yes
2^9	512	512	Yes
2^{10}	1024	1024	No

Three-digit powers of 2:

- $2^7 = 128$
- $2^8 = 256$
- $2^9 = 512$

Total = 3 numbers

4 Shortcut / CSAT Trick

- Use powers of 2: $64 < 100 < 128$ and $512 < 1000 < 1024$. So, $2^7, 2^8, 2^9$ are the only three-digit powers.

5 Final Answer

ANSWER: (c) 3



FROM THE ARCHIVES

Know your English

S. Upendran

Here comes the future chemist. How was the test? How did you do?"

"Pretty bad, actually. The only person who said that he had done a good job was Rahul."

"Rahul? You mean Vijay Kumar's son?"

"The very same, the....the.... 'hair' toHow do you pronounce 'heir'? I always get confused."

"H..e..i..r is pronounced like the word 'air'."

"But I have heard many people pronounce it like h..a..i..r."

"That's true. But it's pronounced like 'air'. You were saying something about Rahul?"

"He is really smart. You know he works really hard. I don't understand why the heir to millions should work so hard."

"You have to work hard in order to make more money."

"I wish I were heir to...."

"...why don't you get somebody rich to adopt you?"

"Not a bad idea, actually. Maybe I can get Rahul's father to adopt me! I think I shall inform him your idea."

"Inform him of."

"What?"

"I think I shall inform him of your idea."

You don't inform someone something, you inform someone 'of something', or 'about' something."

"I see. How does this sentence sound? The Cabinet Secretary informed the Minister of the mine disaster."

"Sounds good. The students informed the Principal of the drug problem on campus."

"We informed the Bank Manager of our new address."

"Tell me, have you ever been to Rahul's house?"

"....I have been there only once. It's huge. We went to downstairs and the rooms...."

a lot of computer games. So...."

"...you spent a lot of time playing computer games!"

"Unfortunately, no. Rahul's mother prevented us to play on the computer."

"You don't 'prevent someone to do something'. You usually 'prevent someone from doing something.'"

"Prevent from, eh? That's interesting."

How about this example? The students were prevented from entering the college by the police."

"downstair."

"Very good. Instead, you simply say, 'Come upstairs', or 'Go downstairs'."

"Just like 'Come here', or 'Go there'."

"That's right. Anyway, what did you do in Rahul's house?"

"We played a lot of table tennis. He has a lot of computer games. So...."

"...you spent a lot of time playing computer games!"

"Unfortunately, no. Rahul's mother prevented us to play on the computer."



- Importance of discussion & curiosity in learning.
- Effective communication improves understanding.



- Correct pronunciation: heir (air) ≠ hair (hair).
- Homophones can create confusion in spoken English.



- Hard work leads to success.
- Effort is essential regardless of wealth or privilege.



- You have to work hard in order to make more money.
- Value of effort and merit.



- Use inform someone of/about something.
- Example: informed the Minister of the disaster.



- 'To downstairs' / 'to upstairs' are incorrect.
- Use: go downstairs / come upstairs.



- Use prevent someone from doing something.
- Example: prevented from entering the college.



- Humour in conversation makes learning enjoyable.
- Context helps in remembering rules better.



- English is about usage + clarity + correctness.
- Practice through real-life conversations.

Stay with the evidence

Better monitoring of sale of banned drugs is essential

The character of science leans to openness: to new evidence and emerging facts. Its ability to be agile to pivot and shift to newer guidelines is therefore absolutely crucial. The Health Ministry's recent ban on 16 Fixed Dose Combination (FDC) drugs comes on the evidence that these drug combinations lack therapeutic justification, are 'deemed irrational or unsafe' and might pose risks to patients. The drugs include dermatological drugs, analgesics and antispasmodics, and antibiotic-based formulations. An FDC is a drug containing two or more active pharmacological ingredients, combined in a fixed ratio in a single dosage. These were meant to improve treatment compliance in chronic conditions (such as Tuberculosis) by reducing the pill burden and, sometimes, by improved therapeutic effectiveness. However, irrational combinations, besides being ineffective, can also be counter-productive and harmful.

As per the latest order, all State Drug Controllers, regulatory authorities, and enforcement agencies are to ensure strict implementation and compliance with the recent notification. Instructions must also be sent to manufacturers, importers, distributors, and even individual pharmacies, to stop stocking and selling the banned FDCs.

This is not the first time that the Health Ministry is cracking down on FDCs. A detailed scientific review is undertaken before these decisions to ban FDCs are taken. In March 2016, the government banned a whopping number of over 330 FDC drugs, on the ground that they were irrational, with immediate effect. While FDCs offer the advantage of a reduction in the number of pills, of certain benefit to certain categories of patients, there are some innate issues as well: patients might need different titrations of doses, impossible with FDCs; patients might develop allergies, but it will not be clear what particular pharmaceutical ingredient they are reacting to. It is also clear that all patients may not actually need to unnecessary side effects might develop from the ban reach the last mile.

A further potential harm exists with FDCs of antibiotics: in 2016, 19% of the 330 FDCs banned were antibiotics; There is enough evidence to show that irrational antibiotic FDC drug usage leads to or exacerbates the growing antimicrobial resistance problem in the country.

While the government has taken a positive step with banning these FDCs, its work has just begun. In many instances in the past, stocks drugs were still being sold in pharmacies, because the message had not percolated down. While staying solidly on the side of evidence-based medicine, the government must also activate its monitoring and supervision arm in order to ensure that the benefits



- Health Ministry banned 16 FDC drugs.
- Evidence shows lack of therapeutic justification.
- Deemed irrational/unsafe and risky for patients.



- FDC = Fixed Dose Combination.
- Contains two or more active ingredients in a fixed ratio.
- Combined in a single dosage form.



- Aim: Improve treatment compliance.
- Reduce pill burden in chronic conditions like Tuberculosis.
- Sometimes improves therapeutic effectiveness.



- Irrational combinations can be ineffective.
- Can be counter-productive and harmful.
- May pose risks to patients.



- All State Drug Controllers and enforcement agencies to ensure strict compliance.
- Instructions to manufacturers, importers, distributors and pharmacies.
- Stop stocking and selling banned FDCs.



- Patients may need different dose titrations.
- Allergies may occur; ingredient responsible may be unclear.
- Not all patients may need all drugs in combination.



- Antibiotic FDCs pose risk of antimicrobial resistance (AMR).
- In 2016, 19% of 330 banned FDCs were antibiotics.
- Irrational antibiotic combinations worsen AMR.



- Banning is a positive step but not the end.
- In the past, banned drugs were still sold.
- Need strong monitoring and awareness.



- Evidence-based medicine must guide decisions.
- Active monitoring and supervision are essential.
- Goal: Ensure benefits of ban reach the last mile.

Deadly fumes

Strict enforcement of safety norms is absent in many industrial units

Tamil Nadu has witnessed its deadliest industrial ammonia gas leak tragedy, which has so far claimed the lives of eight migrant women workers at a private seafood processing unit in Tiruvallur district. Some of the 68 hospitalised workers are in intensive care on oxygen support. Since the 1980s, the State has battled ammonia leaks in factories every few years, mostly in and around Chennai. Other than in Thoothukudi in 2024, where one worker died, such accidents have at worst led to the hospitalisation of large numbers of people with eye irritation and breathing difficulties. There were no casualties even when an estimated 67.638 tonnes of ammonia leaked from the undersea pipeline of a private company in Ennore during Cyclone Michaung in 2023. The scale of the tragedy at St. Peter & Paul Seafood Exports Pvt. Ltd., Tiruvallur, indicates that the colourless pungent gas may have accumulated in the atmosphere at fatal concentrations. The leak occurred when workers were resting in factory accommodation, on Sunday. Had the incident occurred on a working day, the number of people exposed to the leak from the ammonia pipeline to the ice-flake machinery could have been significantly higher.

While a committee comprising the Director of Industrial Safety and Health (DISH), the Member Secretary of the TN Pollution Control Board, and the Additional Director of Public Health is conducting an inquiry, disturbing facts have emerged. The factory reportedly failed to rectify serious deficiencies, pointed out during an earlier DISH inspection, including the absence of a suitable alarm system and fire hydrant. It had also not obtained a revised plan approval for installing an ice-flaking machine. That matter is sub judice. Investigations will reveal whether these shortcomings had any bearing in this tragedy. What is clear, however, is that had the recommendations made by DISH in the Ennore case been universally enforced in factories using ammonia, the scale of the current tragedy could have been contained. DISH had recommended the provision of adequate ammonia sensors in the plant and surrounding areas for early warning, along with water-curtain systems linked to ammonia alarms and fire-water nozzles for ammonia feed pumps to reduce the impact of leaks. The government has now decided to form a committee to inspect all 6,669 hazardous industries. However, numerous checks and balances exist under the Tamil Nadu Control of Industrial Major Accident Hazards Rules, 1994. What is required is strict enforcement through a coordinated approach, stronger penalties for violators, and the political will to act decisively against them.



- Deadliest industrial ammonia gas leak in Tamil Nadu.
- 8 migrant women workers dead; 68 hospitalised.
- Incident at private seafood unit in Tiruvallur.
- Raises concerns over safety lapses in industrial units.



- Ammonia is a colourless, pungent and highly toxic gas.
- Can accumulate in the air and reach fatal concentrations.
- Leak occurred during rest hours; on a working day, casualties could have been much higher.



- Factory failed to rectify serious deficiencies.
- Lack of alarm system and fire hydrant.
- No revised plan approval for installing ice-flaking machine.
- Violations despite earlier DISH inspection.



- Inquiry by committee: DISH, TNPCB, and Public Health.
- Matter is sub judice; investigations ongoing.
- Focus on compliance failures and their role in tragedy.



- DISH had earlier recommended:
 - Ammonia sensors for early warning.
 - Water-curtain systems linked to alarms.
 - Fire-water nozzles for feed pumps.



- Govt. to inspect all 6,669 hazardous industries.
- Strong legal framework exists under TN Control of Industrial Major Accident Hazards Rules, 1994.



- Need strict enforcement of safety norms.
- Coordinated approach and stronger penalties.
- Political will essential to prevent such tragedies.

KEY TAKEAWAYS

- Industrial safety lapses can lead to catastrophic loss of life.
- Early warning systems and safety compliance are non-negotiable.
- Enforcement and political will are crucial.
- Protecting workers' lives must be the top priority.

The challenge of India's digital sovereignty

In the modern world, digital infrastructure is the track on which commerce, government, and national security run.

Seen in this context, recent reports of Indian closed-circuit television (CCTV) networks being compromised by hostile entities to gain access to information on India's strategic defence assets (April 2026), along with an incident in July 2025, in which Nayara Energy was abruptly denied access to its corporate email, collaboration tools, and cloud-stored data, raise serious concerns about the future of India's digital and technological sovereignty. While the CCTV security breach was attributed to the use of the Chinese software platform EseeCloud in the CCTV equipment, the Nayara episode was a result of Microsoft Corporation's unilateral enforcement of European Union (EU) sanctions against Nayara Energy due to the stake held in it by the Russian energy giant Rosneft.

These incidents have exposed an uncomfortable reality: critical Indian digital infrastructures such as authentication systems, productivity suites, and cloud platforms operate on technology platforms owned and operated by foreign technology giants. Even when data is physically stored in India, under certain existing global data governance regimes, foreign cloud technology companies can be compelled to provide data within their possession to their home governments. As a result, effective control over digital infrastructure shifts away from Indian entities to overseas corporations and foreign governments.

Foreign control, national risk

The major implication is that the functioning of Indian businesses and critical government services built on foreign technology platforms becomes vulnerable to decisions made by external sovereigns. Directives issued by external sovereigns to deny access to critical digital technology to Indian entities could suspend government operations, collapse trade and commerce, halt manufacturing, and weaken defence capabilities.

For instance, since contemporary warfare is software-defined, the intelligence embedded in fighter aircraft, missile systems, and advanced radar installations resides not in hardware but in code that remains under the control of manufacturers answerable to foreign governments. In conflict scenarios, these manufacturers could possibly degrade targeting accuracy, reduce operational range, or worse, redirect battlefield intelligence to adversaries due to instructions from external sovereigns, all through software configuration changes. A case in point is the 1999 Kargil conflict, during which



Manish Verma

Technology Strategist, Distinguished Fellow at Avinyum Foundation, a not-for-profit technology think tank, and a PhD (Practice Track) Scholar at the Indian Institute of Management Kozhikode



Sthanu R. Nair

Teaches Economics and Public Policy at the Indian Institute of Management Kozhikode

Digital sovereignty is essential for India's technological security and strategic autonomy

India faced limitations on access to precise GPS support at a moment when navigation and targeting in mountainous terrain were operationally decisive.

India's unique situation

The vulnerability and the risks of dependence on foreign digital infrastructure are being recognised globally. France plans to shift government departments from Microsoft Teams and Zoom to a sovereign video-conferencing platform by 2027. The Netherlands, Denmark, and several German states are exploring domestic alternatives to critical United States software and cloud services such as Microsoft Word, Excel, Outlook, and Teams. The EU is seeking to reduce its dependence on American technology through independent European cloud and IT infrastructure, while Türkiye is lessening its reliance on foreign technologies.

However, unlike other nations, India's situation is uniquely precarious when contextualised within the framework of Power Transition Theory, which posits that when a rising power, desirous of maintaining strategic autonomy, approaches parity with an established hegemon, the latter invariably acts to constrain the former. History demonstrates that rising competitors are contained or co-opted. We already see it being played out on a much larger scale between the U.S. and China. With an accelerating growth trajectory, India has been inching towards this critical zone while facing a daunting task: building its economic fortune on a technology infrastructure independent of foreign influence.

The strategy to address this challenge must be multipronged. The denial of GPS access during the Kargil conflict spurred India to develop its own satellite navigation system. More recently, efforts to strengthen the domestic semiconductor ecosystem and migrate the email systems of some central government ministries to the homegrown Zoho platform reflect a growing commitment to digital and technological sovereignty. India's success in building indigenous payments infrastructure through UPI and RuPay has shown that vulnerabilities arising from foreign-controlled systems can be overcome. This model can be extended to cloud infrastructure, e-commerce platforms, authentication systems, and defence technologies.

To de-risk dependence on foreign defence technologies, India could emulate aspects of the U.S.'s defence production and procurement model. While India has long recognised the importance of self-reliance in defence manufacturing, its heavy reliance on the public sector has not delivered the desired results. The absence of an indigenous modern fighter aircraft

despite the programme having begun in the 1980s is a stark reminder of this shortcoming. In contrast, American defence platforms are largely developed by private corporations, with the government providing research funding and assured procurement. This creates a virtuous cycle in which companies develop cutting-edge capabilities while remaining aligned with national strategic interests. India has recently begun moving in this direction by inviting private-sector participation in the development of the Advanced Medium Combat Aircraft under a competitive framework.

Another way to safeguard digital sovereignty is to develop critical technologies and digital infrastructure in partnership with other countries. This ensures mutual dependence, reducing the risk of unilateral actions that could undermine India's strategic interests. The BrahMos missile programme, jointly developed by India and Russia, is a notable example. A key advantage of this approach is that it enables India to build technological capabilities without risking international isolation, unlike China which allowed only indigenous companies to develop critical technologies. Seen in this context, two recent developments are encouraging. The first is the country's semi-conductor production, Test, Marking and Packaging (ATMP) facility in Sanand, Gujarat, established through India-U.S. technology cooperation. The second is India's decision to join Pax Silica, the U.S.-led initiative on AI and supply-chain security aimed at reducing dependence on Chinese technology and strengthening trusted technology partnerships.

Close the R&D gap

Above all, India must urgently raise its research and development (R&D) spending to levels comparable with global leaders. India's gross expenditure on R&D averaged just 0.74% of GDP between 2000 and 2020 against a global average of 2.07%. This persistent R&D spending deficit raises serious concerns about India's future technological and digital sovereignty. For a country of India's demographic scale and economic ambitions, seeking to approach parity with established powers, the question is not whether it can afford comprehensive technological sovereignty, but whether it can afford to forgo it. The extent to which India succeeds in mitigating the risks to its technological sovereignty will determine its economic competitiveness and strategic autonomy in an increasingly fragmented international order.

Key Concerns

- Indian digital infrastructure dependent on foreign tech platforms.
- Foreign control over data poses national security and strategic risks.

National Risk

- Foreign sovereigns can restrict access to critical systems.
- Can disrupt governance, defence, trade, and commerce.

Global Trends

- EU, France, Netherlands, Denmark, Germany, Türkiye reducing dependence on US tech.
- Moving towards sovereign digital infrastructure.

India's Response

- Develop indigenous systems (NaviC, UPI, RuPay).
- Strengthen semiconductor, cloud, and email autonomy.
- Build tech infrastructure independent of foreign influence.

Strategic Path

- Promote private sector in defence R&D.
- Partner with trusted nations (BrahMos model).
- Join global initiatives (Pax Silica).

Way Forward

- Increase R&D spending to global levels.
- Build self-reliance in critical technologies.
- Ensure long-term digital and technological sovereignty.

त्वरित समाचार (10)

1. IAEA निरीक्षक हाल की वार्ताओं के बाद ईरान लौट सकते हैं।
2. J.D. वेंस ने कहा, अमेरिका-ईरान वार्ता में प्रगति हो रही है।
3. होरमुज़ जलडमरूमध्य में घटनाओं को रोकने का तंत्र प्रस्तावित।
4. बिजली उत्पादन बढ़ा, जबकि इस्पात वृद्धि 16 महीने के निचले स्तर पर।
5. RBI ने रेपो दर को 6.00% पर यथावत रखा।
6. मई 2026 में भारत का सेवा PMI 60.8 पर पहुँचा।
7. IMD ने जून-जुलाई के लिए सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान लगाया।
8. NITI आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी किया।
9. ISRO ने अर्थ अवलोकन उपग्रह EOS-09 लॉन्च किया।
10. सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रोरल बॉन्ड्स योजना को बरकरार रखा।

प्रिलिम्स तथ्य (12)

1. होरमुज़ जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है।
2. IAEA HQ: वियना, ऑस्ट्रिया।
3. BRICS 2026 अध्यक्षता: भारत।
4. BRICS सदस्य: ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका।
5. ब्रह्मोस: भारत (DRDO) और रूस (NPOM) का संयुक्त उपक्रम।
6. आकाशतीर: स्वदेशी वायु रक्षा कमांड एवं नियंत्रण प्रणाली।
7. अमोनिया (NH₃): रंगहीन गैस, अत्यधिक उत्तेजक।
8. MeitY: इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।
9. AnSI HQ: कोलकाता, पश्चिम बंगाल।
10. राखीगढ़ी: सिंधु घाटी सभ्यता स्थल, हिसार जिला, हरियाणा।
11. RTI अधिनियम लागू: 2005।
12. SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24: निति आयोग की पहल।

शब्दावली (7)

1. संप्रभुता (Sovereignty) — सर्वोच्च अधिकार या स्वतंत्रता।
2. विषमता (Asymmetry) — असमानता या असंतुलन की स्थिति।
3. पारदर्शिता (Transparency) — स्पष्टता और खुलापन।
4. विवेकाधिकार (Arbitrariness) — मनमाने ढंग से निर्णय लेना।
5. अंतरविषयक (Interdisciplinary) — अनेक विषयों से संबंधित अध्ययन।
6. तर्कसंगतता (Rationality) — तर्क और बुद्धि पर आधारित सोच।
7. जवाबदेही (Accountability) — उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी।

1 UAE भारत से ब्रह्मोस मिसाइल और आकाशतीर एयर-डिफेंस यूनिट खरीदने पर बातचीत में

- UAE भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और आकाशतीर वायु रक्षा प्रणाली खरीदने पर विचार कर रहा है।
- यह रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगा।
- भारत के स्वदेशी रक्षा उद्योग और निर्यात को बढ़ावा।
- हिंद महासागर और खाड़ी क्षेत्र में भारत की सामरिक उपस्थिति सुदृढ़ होगी।
- 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में महत्वपूर्ण कदम।



स्टैटिक लिंक: रक्षा निर्यात, DRDO, ब्रह्मोस, आकाश, आत्मनिर्भर भारत
UPSC एंगल: GS III – रक्षा, टेक्नोलॉजी, अंतरराष्ट्रीय सहयोग
वन-लाइनर: यह डील भारत की वैश्विक रक्षा साझेदारी को नई ऊँचाई देगी।

2 डोभाल ने पश्चिम एशिया तनाव के बीच BRICS देशों के NSA की बैठक की मेजबानी की

- NSA अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में BRICS NSA बैठक की मेजबानी की।
- पश्चिम एशिया की स्थिति, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा मुख्य विषय रहे।
- BRICS देशों ने बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था और सुरक्षा सहयोग पर पुनः प्रतिबद्धता जताई।
- वैश्विक दक्षिण की आवाज को सशक्त करने और नेतृत्व मजबूत करने पर जोर।



स्टैटिक लिंक: BRICS, बहुयुवीयता, वैश्विक सुरक्षा
UPSC एंगल: GS II – अंतरराष्ट्रीय संबंध
वन-लाइनर: BRICS संवाद वैश्विक दक्षिण की एकजुटता को मजबूत करता है।

3 'घातक गैस': तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव

- सीफुड प्रोसेसिंग यूनिट में अमोनिया गैस लीक, कई लोगों की मौत।
- औद्योगिक सुरक्षा मानकों में गंभीर कमी उजागर।
- प्रवासी श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित।
- रासायनिक जोखिम प्रबंधन और मॉनिटरिंग जरूरी।
- आपदा तैयारी और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता।



स्टैटिक लिंक: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, MSIHIC नियम, 1989
UPSC एंगल: GS III – आपदा प्रबंधन, पर्यावरण, श्रम कल्याण
वन-लाइनर: औद्योगिक सुरक्षा ही जनजीवन और सतत विकास की कुंजी है।

4 भारत की डिजिटल संप्रभुता की चुनौती

- डेटा निर्भरता, विदेशी प्लेटफॉर्म और क्लाउड पर निर्भरता एक बड़ा जोखिम।
- डेटा स्थानीयकरण, साइबर सुरक्षा और डिजिटल एकाधिकार प्रमुख मुद्दे।
- सुरक्षित डिजिटल अवसंरचना और स्वदेशी प्रौद्योगिकी आवश्यक।
- 21वीं सदी में डिजिटल संप्रभुता ही रणनीतिक स्वायत्तता का आधार है।
- अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और नागरिक गोपनीयता के लिए महत्वपूर्ण।



स्टैटिक लिंक: डेटा संरक्षण अधिनियम, MeitY, डिजिटल इंडिया
UPSC एंगल: GS III – S&T, सुरक्षा, शासन
वन-लाइनर: डिजिटल संप्रभुता भविष्य की शक्ति और स्वतंत्रता की रीढ़ है।

5 वह विश्व जो चीन चाहता है और गढ़ रहा है

- चीन 'चीन-केंद्रित' वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है।
- BRI, AIIB, डिजिटल युआन से प्रभाव विस्तार।
- उदार लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थानों के लिए चुनौती।
- इंडो-पैसिफिक, अफ्रीका और सेंट्रल एशिया में रणनीतिक उपस्थिति।
- भारत को बहुआयामी रणनीति और साझेदारी मजबूत करनी होगी।



स्टैटिक लिंक: BRI, AIIB, इंडो-पैसिफिक, बेल्ट एंड रोड
UPSC एंगल: GS II – अंतरराष्ट्रीय संबंध, भू-राजनीति
वन-लाइनर: चीन की वैश्विक दृष्टि को समझना भारत की रणनीति का आधार है।

6 कानून का एकाधिकार किसी का नहीं: सरकारी मानक सार्वजनिक होने चाहिए

- सरकारी मानक (नियम, कोड, नॉर्म्स) सार्वजनिक डोमेन में हों।
- सूचना की असमानता और मनमानी को रोकता है।
- पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक विश्वास को बढ़ाता है।
- आसान अनुपालन से व्यवसाय को सुविधा।
- लोकतांत्रिक शासन के लिए सार्वजनिक विधिक पहुँच अनिवार्य।



स्टैटिक लिंक: RTI अधिनियम, पारदर्शिता, विधि का शासन
UPSC एंगल: GS II – सुशासन
वन-लाइनर: सार्वजनिक मानक ही निष्पक्ष और प्रभावी शासन की गारंटी हैं।

7 IITs में घुसा ट्रोजन हॉर्स

- IITs में अंधविश्वास और अवैज्ञानिक विचारधाराओं का प्रवेश चिंता का विषय।
- शोध की गुणवत्ता और अकादमिक स्वतंत्रता पर खतरा।
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कशीलता आवश्यक।
- भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश हो, परंतु विज्ञान-विरोध नहीं।
- IITs को नवाचार और वैज्ञानिक उत्कृष्टता के केंद्र बने रहना चाहिए।



स्टैटिक लिंक: शिक्षा नीति 2020, वैज्ञानिक दृष्टिकोण
UPSC एंगल: GS II – शिक्षा, संस्थान, अनुसंधान
वन-लाइनर: विज्ञान और तर्क ही IITs की पहचान और शक्ति हैं।

8 साक्ष्यों पर टिके रहें (Stay with the Evidence)

- साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण सर्वोत्तम शासन की आधारशिला।
- गलत जानकारी, पक्षपात और लोफप्रिय आख्यानों से बचें।
- संस्थानों और सार्वजनिक विमर्श को मजबूत करता है।
- डेटा, अनुसंधान और वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा देता है।
- तर्कसंगत, नैतिक और प्रभावी निर्णयों की नींव।



स्टैटिक लिंक: नीति आयोग SDGs, साक्ष्य-आधारित नीति
UPSC एंगल: GS IV – नैतिकता, ईमानदारी, तर्कशीलता
वन-लाइनर: साक्ष्य ही सत्य तक पहुँचने का मार्ग है।

9 ASI ने राखीगढ़ी कंकाल AnSI को वैज्ञानिक जांच के लिए दिए

- ASI ने राखीगढ़ी से प्राप्त मानव कंकाल AnSI को सौंपे।
- यह स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा ज्ञात स्थल है।
- प्राचीन DNA, आहार, वंशावली और प्रवासन पैटर्न का अध्ययन होगा।
- भारतीय पुरातत्व और मानवशास्त्र अनुसंधान को नई दिशा।
- भारत के प्राचीन इतिहास को समझने में मदद मिलेगी।

स्टैटिक लिंक: सिंधु घाटी सभ्यता, ASI, AnSI, मानवशास्त्र
UPSC एंगल: GS I – इतिहास, संस्कृति
वन-लाइनर: विज्ञान और पुरातत्व्य मिलकर भारत के प्राचीन अतीत को उजागर करेंगे।



1 UAE in Talks with India to Purchase BrahMos Missiles and Akashteer Air-Defence Units

- UAE in advanced talks to buy BrahMos supersonic missiles and Akashteer air-defence command system.
- Strengthens India's defence exports and strategic partnership with UAE.
- Supports Atmanirbhar Bharat and Make in India in defence.
- Enhances India's influence in the Gulf region.
- Builds on existing defence cooperation and interoperability.



Static Link: Defence exports, DRDO, BrahMos, Akashteer
UPSC Angle: GS III – Defence, Indigenisation, IR partnerships
VA: Boosts India's role as net security provider in the region.

2 Doval Hosts NSAs of BRICS Nations Amid West Asia Tensions

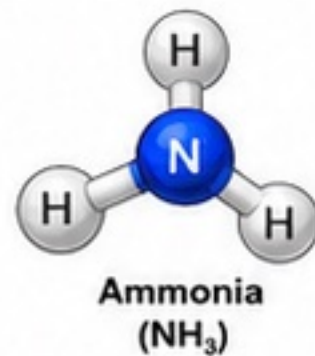
- NSA Ajit Doval hosted BRICS NSA meeting in New Delhi.
- West Asia tensions dominated discussions.
- Focus on counter-terrorism, cyber security, food & energy security.
- Reaffirms BRICS commitment to multipolar world order.
- Boosts India's leadership in global security dialogue.



Static Link: BRICS, Multipolarity, Global Security
UPSC Angle: GS II – International Relations
VA: Strengthens Global South unity in a volatile world.

3 'Deadly Fumes': Ammonia Gas Leak in Tamil Nadu

- Ammonia gas leak at seafood processing unit in T.N. caused casualties.
- Highlights poor industrial safety and hazardous chemical handling.
- Large migrant workforce at risk due to weak safety compliance.
- Calls for stricter enforcement of safety norms and audits.
- Need for robust disaster preparedness and response.



Static Link: Disaster Management Act, MSIHC Rules, 1989
UPSC Angle: GS III – Disaster Management, Environment
VA: Industrial safety is critical for sustainable development.

4 The Challenge of India's Digital Sovereignty

- India faces risks from data dependence on foreign platforms.
- Issues: data localisation, cybersecurity, cloud dependence, digital monopolies.
- Need for secure digital infrastructure and indigenous technologies.
- Digital sovereignty = strategic autonomy in the 21st century.
- Critical for economy, security and citizen privacy.



Static Link: Data Protection Act, MeitY, Digital India
UPSC Angle: GS III – S&T, Security, Governance
VA: Digital sovereignty is the backbone of future power.

5 The World that China Desires and Is Shaping

- China promotes a 'China-centric' global order.
- Expanding influence via BRI, AIIB, digital yuan, and tech dominance.
- Challenges liberal democratic values and existing institutions.
- Seeks strategic space in Indo-Pacific, Africa, and Central Asia.
- India must balance engagement with safeguarding interests.



Static Link: BRI, Quad, Indo-Pacific, Belt & Road Initiative
UPSC Angle: GS II – IR, Geopolitics
VA: Understanding China's worldview is key to India's strategy.

6 No One Should Own the Law: Why Government Standards Should Be Public

- Govt standards (rules, codes, norms) must be in public domain.
- Prevents information asymmetry and arbitrary enforcement.
- Enhances transparency, accountability and citizen trust.
- Supports ease of doing business and innovation.
- Democratic governance requires public legal access.



Static Link: RTI Act, Transparency, Rule of Law
UPSC Angle: GS II – Governance
VA: Public standards ensure fair governance and compliance.

7 A Trojan Horse Has Breached the IITs

- Debate over penetration of unscientific and non-evidence-based ideologies.
- Risks to scientific temper and academic freedom.
- Need to preserve merit, research quality and rigour.
- Indian Knowledge Systems should complement, not replace, science.
- Safeguarding IITs is vital for India's knowledge leadership.



Static Link: Education Policy, Scientific Temper
UPSC Angle: GS II – Education, IKS, Institutions
VA: IITs must remain centres of innovation and evidence.

8 Stay with the Evidence

- Evidence-based policymaking is essential for good governance.
- Resists misinformation, bias and populist narratives.
- Strengthens institutions and public trust.
- Encourages data, research and scientific validation.
- Foundation of rational, ethical and effective decisions.



Static Link: NITI Aayog, SDGs, Evidence-based Policy
UPSC Angle: GS IV – Ethics, Integrity, Aptitude
VA: Evidence builds credibility and long-term impact.

9 ASI Transfers Rakhigarhi Skeletons to AnSI for Scientific Investigation

Static Link: Harappan Civilisation, ASI Act, AnSI
UPSC Angle: GS I – History, Culture
VA: Science & archaeology together unlock India's ancient past.

- ASI transfers Rakhigarhi human skeletons to AnSI for detailed scientific study.
- Rakhigarhi is among the largest Harappan sites in India.
- Study to reveal ancient DNA, diet, ancestry and migration patterns.
- Strengthens scientific archaeology and interdisciplinary research.



QUICK NEWS (10)

1. IAEA inspectors may return to Iran after recent talks.
2. J.D. Vance says U.S.-Iran talks are making progress.
3. Mechanism proposed to prevent incidents in Strait of Hormuz.
4. Electricity output grows while steel growth slows to 16-month low.
5. RBI keeps repo rate unchanged at 6.00%.
6. India's services PMI rises to 60.8 in May 2026.
7. IMD forecasts above-normal southwest monsoon.
8. NITI Aayog releases SDG India Index 2023-24.
9. ISRO to launch Earth observation satellite EOS-09.
10. Supreme Court upholds electoral bonds scheme.

PRELIMS FACTS (12)

1. Strait of Hormuz connects Persian Gulf to Gulf of Oman.
2. IAEA HQ: Vienna, Austria.
3. BRICS 2026 Chair: India.
4. BRICS Members: Brazil, Russia, India, China, South Africa.
5. BrahMos: Joint venture of India (DRDO) & Russia (NPOM).
6. Akashteer: Indigenous air-defence command system.
7. Ammonia (NH₃): Colourless gas, highly irritating.
8. MeitY: Ministry of Electronics & Information Technology.
9. AnSI HQ: Kolkata, West Bengal.
10. Rakhigarhi: Indus Valley site in Hisar district, Haryana.
11. RTI Act enacted: 2005.
12. SDG India Index 2023-24: NITI Aayog initiative.

VOCABULARY (7)

1. Penetration – Gradual entry or infiltration.
2. Asymmetry – Lack of equality or balance.
3. Sovereignty – Supreme authority or independence.
4. Arbitrary – Based on individual discretion.
5. Interdisciplinary – Involving multiple fields of study.
6. Rigour – Strictness in procedure or method.
7. Accountability – Responsibility for one's actions.